component Plan concerning their respective programme and also indicate specific financial allocations thereof within their overall Annual/Five Year Plans.

अवैध निर्माण को रोकने के लिए विधेयक

753. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निजी भवन निर्माताओं, एस्टेट एजेंटों और प्रापर्टी डीलरों की अवैध निर्माण गतिविधियों को कड़ाई से रोकने के लिए सरकार द्वारा तैयार एक विधेयक दिल्ली राज्य सरकार के पास भेजा गया था और यह उनके पास लंबित पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शहरी भूमि, परिसीमन और नियमन अधिनियम के निरस्त होने के बाद यह विधेयक और भी जरूरी हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्राइवेट बिल्डरों और प्रापर्टी एजेन्टों के कार्य कलापों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए "दिल्ली रियल ऐस्टेट विकास.विनियमन विधेयक" नामक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। यह विधेयक टिप्पणी हेतु सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजा गया है और इस प्रक्रिया में दिल्ली सरकार से भी परामर्श किया गया है।

(ख) अनुमान है कि शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम के निरसन से आवास निर्माण में तेजी आएगी और इस तीव्र विकास के दौर में इस विधेयक से दिल्ली में बिल्डरों के अध्यवसायी कार्यकलापों को नियंत्रित करना आसान होगा।

(ग) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय विधेयक को अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

Plan to Improve Living Conditions in Slums

754. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a plan is under consideration of the Delhi Government to improve the living conditions in slums;

(b) if so, whether other State Governments are contemplating such plans;

(c) whether a policy is being formulated for slum clusters; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) At present to solve the problem of the slum/JJ cluster, the following three-pronged strategy is being implemented by the Govt. of NCT of Delhi through the Slum Department of MCD:

(i) Where the JJ dwellers have been residing prior to 31.1.90 on land urgently required by the land-owning agency for the execution of a public purpose project, these JJ dwellers are relocated elsewhere through assistance provided by the Government and the land-owning agency.

(ii) In-situ upgradation of JJ colony is resorted to where the land-owning agency does not need the land in the foreseeable future and gives NOC to the effect that such clusters may be upgraded.

(iii) Civic amenities like water supply, street lighting, road, storm water drains, etc. are provided in JJ clusters, which do not fall in categories (i) and (ii) above.

(b) to (d) Slum development is a State subject and each State Government has its own plan and programmes for slum development as per their own priority. However, this Ministry is contemplating formulation of a National Slum Development Policy in consultation with the States. The proposed policy will serve as guide to State Government for drawing up specific plans and programmes for slum improvement/ development works. The Government of India launched a National Slum